भारत के प्रधानमंत्री की अमरीका यात्रा

डॉ.स्तुति बनर्जी *

न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आगामी अमरीका यात्रा और तत्पश्चात वाशिंगटन डी. सी. में (29-30 सितंबर को) अमरीकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा से मुलाकात को अनेक लोगों द्वारा भारत-अमरीका संबंध पर नए सिरे से ध्यान केन्द्रित करने के अवसर के रूप में देखा जा रहा है। दोनों देश बदलते अंतरराष्ट्रीय वातावरण को ध्यान में रखते हुए अपनी-अपनी विदेश नीति को पुन: संरेखित कर रहे हैं। भारत ने अपने कार्यनीतिक विकल्पों को बढ़ाने के लिए सभी प्रमुख ताकतों के साथ संबंधों को आगे ले जाने और अपने द्विपक्षीय संबंधों में सुधार करके एवं विभिन्न बहुपक्षीय संगठनों के माध्यम से बहुध्रुवीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का निर्माण करने का निर्णय लिया है। अमरीकी विदेश विभाग एवं रक्षा विभाग का मानना है कि भारत क्षेत्रीय सुरक्षा का भार साझा करने में ठोस भूमिका निभा सकता है। इससे अमरीका के हितों की रक्षा तो होगी ही, साथ ही उसे सक्रिय भूमिका निभाने से थोड़ा पीछे हटने का मौका भी मिलेगा। अमरीका को इस क्षेत्र में सर्वत्र फैले अमरीका-विरोधी भावनाओं का भान है और शायद भारत इसका एकमात्र अपवाद है। अमरीका भारत के अच्छे संबंधों तथा प्रभाव का लाभ उठाना चाहता है ताकि इस क्षेत्र को स्थिर बनाने में सहायता मिल सके जो कट्टरपंथी राजनीति के उत्थान, *नॉन-स्टेट एक्टर्स* और आतंकी संगठनों के बढ़ते प्रभाव और इसके सापेक्ष अमरीका के घटते प्रभाव का साक्षी बना हुआ है।

अमरीका के लिए भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा का इससे सुनहरा अवसर नहीं हो सकता था। यह (अमरीका) मध्य पूर्व की अपनी नीति पर पुनर्विचार की प्रक्रिया में है। यूक्रेन के संकट ने भी सुनिश्चित किया है कि अमरीका अपने पश्चिमी गुट के सहयोगियों को निश्चित 'सुरक्षा कवच' उपलब्ध कराता है। यह 'धीरे-धीरे अफगानिस्तान से अपनी वापसी' की योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है। ऐसी परिस्थिति

में, अमरीका दक्षिण एशिया क्षेत्र में एक सुरक्षित तथा स्थिर वातावरण बनाए रखने में सहायता के लिए भारत की ओर एक सहयोगी के रूप में देख रहा है। भारत की नई सरकार ने पड़ोस के देशों से संबंधों में सुधार करने को जो महत्व दिया है, उससे अमरीका अवगत है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार के शपथ-ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए पड़ोसी राष्ट्राध्यक्षों एवं सरकारों को निमंत्रण देने के बाद प्रधानमंत्री सहित सरकारी अधिकारियों तथा मंत्रियों ने पड़ोसी देशों के दौरे किए। इससे भारत को अपने पड़ोसियों के बीच सद्भावना सृजित करने में सहायता मिली है। पदभार ग्रहण करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का पहला दौरा भूटान का था, जिससे भूटानी नेताओं को संकेत गया कि नई दिल्ली के लिए थिंपु की भागीदारी कितना महत्व व मायने रखती है। न केवल राजनीतिक प्रतिष्ठानों से बल्कि नेपाल की जनता से भी जैसी सकारात्मक प्रतिक्रिया इनके दौरे को मिली, वह असाधारण था। अमरीका ने फोर्टलेज़ा, ब्राजील में संपन्न वार्ताओं के दौरान ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन व दक्षिण अफ्रीका) के नेताओं तक प्रधानमंत्री मोदी की आउटरीच पर पैनी नजर रखी है। आर्थिक संबंधों में सुधार करने तथा रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग को और बढ़ाने के लिए इनकी (भारतीय प्रधानमंत्री की) हाल की जापान यात्रा का भी अमरीका ने गहरी रूचि के साथ संज्ञान लिया है। इन बैठकों के दौरान दिए गए वक्तव्य अपनी सुरक्षा सुदृढ़ करने और अपने आर्थिक संबंधों का विस्तार करने की दृष्टि से संपर्क बढ़ाने की भारत की नीति के द्योतक हैं। इससे वाशिंगटन में यह अवधारणा पैदा हुई है कि भारत अपनी विदेश नीति के निर्णयों में मुखर रहेगा, क्योंकि इस सरकार को राजनीतिक बहुमत और लोकप्रिय समर्थन प्राप्त है।

प्रधानमंत्री मोदी की आगामी अमरीका यात्रा अपने साथ विश्व के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच संबंधों में अर्थपूर्ण अभिप्राय लेकर आई है। दोनों नेताओं से "अमरीका-भारत कार्यनीतिक भागीदारी का विस्तार करने तथा इसे और प्रगाढ़ बनाने हेतु परस्पर हित के कई मुद्दों पर चर्चा करने की उम्मीद है। वे (दोनों नेता) आर्थिक विकास की गति तेज करने, सुरक्षा सहयोग सुदृढ़ करने और वैसी क्रियाकलापों में सहयोग करने के तरीके पर विचारविमर्श करेंगे जो दोनों देशों और विश्व को दीर्घकालिक लाभ पहुंचा सके। वे अफगान, सीरिया और इराक, जहां सकारात्मक परिणाम की दिशा में सहयोगी के रूप में भारत और अमरीका मिलकर काम कर सकते हैं, में वर्तमान गतिविधियों सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर भी ध्यान केन्द्रित करेंगे।" ऐसी आशा है कि व्यापार, कराधान, परमाणु और सुरक्षा मुद्दों पर जारी मतभेदों और अमरीकी अप्रवासन कानूनों पर भी चर्चा की जाएगी। ऐसा भी अनुमान है कि इस दौरे से भारत में निवेश हेतु अमरीकी व्यापार को आकर्षित करने हेतु अपेक्षित अवसर पैदा होंगे। प्रवासी भारतीय जो अमरीका की

राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, भी इस उद्देश्य की प्राप्ति में सहयोग करने में अपनी भूमिका पर प्रधानमंत्री को सुनने की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं।

पाकिस्तान से चलाए जा रहे आतंकवाद पर भारतीय चिंता एक अन्य प्रमुख मुद्दा होगा। साथ ही, विशेषकर अपना ध्यान भारत की ओर केन्द्रित करने की अल-कायदा की हाल की घोषणा के बाद, अफगानिस्तान की स्थिति का मुद्दा भी बातचीत के दौरान उठाया जाएगा। कोंसुलर मुद्दे, जैसे, और अधिक भारतीय व्यवसायियों को वीज़ा प्रदान करना, अमरीका में भारतीय कंपनियों को समान अवसर सुनिश्चित करना, ऐसे कुछ अन्य मुद्दे हैं, जिनपर प्रधानमंत्री मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति के बीच चर्चा हो सकती है।

अमरीका नई सरकार द्वारा आर्थिक विकास को दिए गए महत्व से परिचित है और वह भारत के भविष्य के आर्थिक एजेंड़े का हिस्सा बनने को आतुर है। वह रक्षा तथा सुरक्षा क्षेत्र में भी अपनी उपस्थिति बढ़ाने की आशा रखता है। नई सरकार के कार्यकाल संभालने के पहले 100 दिनों के भीतर ही विदेश मंत्री जॉन कैरी, वाणिज्य मंत्री पेनी प्रिट्ज़केर और रक्षा मंत्री चक हेगेल भारत के दौरे पर आए। यह संबंधों को *'पुन: ऊर्जावान बनाने'* और "सही मायने में भारत-अमरीका कार्यनीतिक भागीदारी विकसित करने की अमरीकी प्रशासन की लालसा का संकेतक है ..... (जो) ..... दक्षिण एशियाई क्षेत्र, एशिया और विश्व भर में शांति, स्थिरता और संपन्नता में महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है।" जहां वाइट हाउस तथा अमरीकी विदेश विभाग राजनीतिक क्षेत्र में भारत के साथ संबंधों में सुधार करने में लगे हैं, वहीं पेंटागन विशेषकर दक्षिण एशिया क्षेत्र में सैन्य सहयोग में विस्तार की संभावना तलाश रहा है। अमरीकी रणनीतिक समुदाय यह समझता है कि भारत के साथ मजबूत रक्षा संबंध अमरीका के लिए लाभप्रद होंगे। भारत भी रक्षा अनुसंधान तथा विकास में अग्रणी देश, अमरीका के साथ रक्षा के क्षेत्र में सहयोग से होने वाले लाभों से अवगत है।

भारत के रक्षामंत्री अरूण जेटली अक्तूबर में जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष और विश्व-बैंक की वार्षिक बैठक में हिस्सा लेने के लिए वाशिंगटन जाएंगे तब वे अमरीकी रक्षा मुख्यालय भी जाएंगे। अमरीका इस दौरे से भी कुछ सकारात्मक परिणामों की आशा रखता है।

**डॉ. स्तुति बनर्जी विश्व मामलों की भारतीय परिषद में अनुसंधान अध्येता हैं।*